



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2009/ज्येष्ठ 20, 1931

No. 99]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2009/JYAISTHA 20, 1931

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 10 जून, 2009

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-2010/09/165992.—बोर्ड, प्रतिभूति सचिवा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क के साथ पठित धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30, धारा 11 की उप-धारा (1) तथा धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;

(ii) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है;

(iii) "कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 के अर्थ के भीतर कम्पनी अभिप्रेत है और जिसमें तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित निगमित निकाय या निगम सम्मिलित है, जिसके इक्विटी शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;

(iv) "अनिवार्य सूचीबद्धता" से इन विनियमों के अध्याय V के अधीन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कम्पनी के इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता अभिप्रेत है;

(v) "सार्वजनिक शेयरधारक" या "सार्वजनिक शेयरधारकों" से इक्विटी शेयरों के धारक अभिप्रेत हैं, निम्नलिखित से भिन्न :

(क) संप्रवर्तक;

(ख) अभिरक्षक के द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के प्रति विदेश में जारी निष्पापनार रसीदों (डिपॉजिटरी रसीट) के धारक और ऐसा अभिरक्षक;

(vi) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से कोई वह स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जिसे प्रतिभूति सचिवा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन मान्यता प्रदान की गयी है;

(vii) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(viii) "स्वैच्छिक असूचीबद्धता" से इन विनियमों के अध्याय III के अधीन स्वैच्छा से कम्पनी के आवेदन पर कम्पनी के इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता अभिप्रेत है;

(ix) "कार्य दिवस" (या "कार्य दिवसों") से बोर्ड के कार्य दिवस अभिप्रेत हैं।

(2) शब्दों "नियंत्रण", "सामान्य मति से कार्य करता हुआ व्यक्ति" (या "सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्ति"), "संप्रवर्तक" और "सार्वजनिक शेयरधारिता" के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अधीन उनके लिए नियत हैं।

(3) इन विनियमों में अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम या प्रतिभूति सचिवा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), या उनके किसी कानूनी उपांतर या पुनः अधिनियमित में या के अधीन परिभाषित, शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमितियों में या के अधीन नियत हैं।

अध्याय II

इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता

3. लागू होना.—(1) ये विनियम उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से या ऐसे किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से कम्पनी के इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता पर लागू होंगे, जहां ऐसे शेयर असूचीबद्ध हैं।

(2) इन विनियमों की कोई भी बात रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 424घ के अधीन राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (नेशनल कम्पनी लॉ ट्रायब्युनल) द्वारा मंजूर स्कीम के अनुसरण में की गई किसी असूचीबद्धता पर लागू नहीं होगी, यदि ऐसी स्कीम—

(क) असूचीबद्धता को पूरा करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिकथित करती है; या

(ख) विनिर्दिष्ट दर पर विद्यमान सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास का विकल्प उपलब्ध कराती है।

4. कतिपय परिस्थितियों में असूचीबद्धता अनुज्ञेय नहीं और असूचीबद्धता के लिए शर्तें.—(1) कोई भी कम्पनी, कम्पनी के इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता के लिए आवेदन नहीं करेगी और कोई भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कम्पनी के इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता की अनुज्ञा नहीं देगा :—

(क) कम्पनी द्वारा इक्विटी शेयरों को क्रय द्वारा वापस लिए जाने के अनुसरण में; या

(ख) कम्पनी द्वारा किए गए अधिमानी (प्रेफरेंशियल) आवंटन के अनुसरण में; या

(ग) जब तक कि किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उस वर्ग के इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता से लेकर तीन वर्षों की कालावधि बीत न गयी हो; या

(घ) यदि कम्पनी द्वारा निर्गमित कोई लिखतें, जो उसी वर्ग के इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय हैं जिनकी असूचीबद्धता चाही जाती है, बकाया हैं।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कम्पनी संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता के लिए आवेदन नहीं करेगी और कोई भी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता की अनुज्ञा नहीं देगा।

(3) उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) और (घ) में अंतर्विष्ट कोई भी बात विनियम 6 के खण्ड (क) के अधीन आने वाले इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता के प्रति लागू नहीं होगी।

(4) कोई भी संप्रवर्तक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अध्याय IV के अधीन उपबंधित निकास अवसर या विनियम 23 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में किये गये शेयरों के अर्जन का वित्तपोषण करने के लिए कम्पनी की निधियों को नियोजित नहीं करेगा।

(5) कोई भी संप्रवर्तक या अन्य व्यक्ति—

(क) किसी शेयरधारक या अन्य व्यक्ति को कपट-वर्चित करने के लिए किसी युक्ति, स्कीम या चालाकी का प्रयोग नहीं करेगा; या

(ख) किसी संव्यवहार या व्यवहार में नहीं लगेगा जो किसी शेयरधारक या अन्य व्यक्ति पर कपट या प्रवंचना के रूप में प्रवर्तित होता है; या

(ग) किसी कार्य या व्यवहार में नहीं लगेगा जो कपटपूर्ण, प्रवंचक या छलसाधक है—इन विनियमों के अधीन चाही गई या अनुज्ञात किसी असूचीबद्धता या दिए गए निकास अवसर या किए गए शेयरों के अन्य अर्जन के संबंध में।

अध्याय III

स्वैच्छिक असूचीबद्धता

5. सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्धता.—इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, कम्पनी अपने इक्विटी शेयरों को उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्ध कर सकेगी जहाँ वे सूचीबद्ध हैं या केवल उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से जहाँ वे सूचीबद्ध हैं :

परंतु यह कि उस वर्ग के इक्विटी शेयरों को धारण करने वाले सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को अध्याय IV के अनुसार निकास अवसर दिया जाता है जिनकी असूचीबद्धता चाही जाती है।

6. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में से केवल कुछ से असूचीबद्धता.—कम्पनी अपने इक्विटी शेयरों को ऐसे एक या अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्ध कर सकेगी जहाँ वे सूचीबद्ध हैं और एक या अधिक अन्य मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में उनकी सूचीबद्धता को जारी रख सकेगी, इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन और निम्नलिखित के अध्यधीन—

(क) यदि किसी एक या अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से प्रस्तावित असूचीबद्धता के पश्चात् इक्विटी शेयर

किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध रहें जिसके पास राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनल हैं, तो सार्वजनिक शेयरधारकों को कोई निकास अवसर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है; और

- (ख) यदि प्रस्तावित असूचीबद्धता के पश्चात्, इक्विटी शेयर राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न रहें, तो अध्याय IV के अनुसार असूचीबद्ध किये जाने के लिए चाहे गए इक्विटी शेयरों को धारण करने वाले सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास का अवसर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या कोई अन्य मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो इस संबंध में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये अभिप्रेत है।

7. असूचीबद्धता के लिए प्रक्रिया जहाँ कोई निकास अवसर अपेक्षित नहीं है।—(1) विनियम 6 के खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामले में—

- (क) प्रस्तावित असूचीबद्धता को कंपनी के निदेशक बोर्ड की बैठक में संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाएगा;
- (ख) कंपनी व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक, व्यापक परिचालन वाले एक हिन्दी राष्ट्रीय दैनिक और उस प्रदेश के प्रादेशिक भाषा के एक समाचारपत्र में प्रस्तावित असूचीबद्धता की सार्वजनिक सूचना देगी जहाँ संबद्ध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है;
- (ग) कंपनी अपनी इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता के लिए संबद्ध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन करेगी; और
- (घ) असूचीबद्धता के तथ्य को असूचीबद्धता के पश्चात् तैयार की गई कंपनी की पहली वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन दी गई सार्वजनिक सूचना में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के नामों का जिनसे कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध किये जाने का इरादा है, ऐसी असूचीबद्धता के कारणों का और राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता के जारी रहने के तथ्य का उल्लेख होगा।

(3) उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन किये गये असूचीबद्धता के लिए आवेदन को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, सभी प्रकार से पूर्ण ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस कार्य दिवसों से अनधिक कालावधि के भीतर निपटाया जाएगा।

8. असूचीबद्धता के लिए शर्तें और प्रक्रिया, जहाँ निकास अवसर अपेक्षित है।—(1) अध्याय III के उपबंधों के अधीन अपने इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता चाहने वाली कोई कंपनी, विनियम 6 के खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामले के सिवाय,—

- (क) अपनी बैठक में कंपनी के निदेशक बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी;

- (ख) डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी, ऐसे संकल्प के संबंध में शेयरधारकों को भेजे गए व्याख्यात्मक विवरण में सभी तात्विक तथ्यों को प्रकट करने के पश्चात् :

परंतु यह कि विशेष संकल्प पर कार्रवाई की जाएगी यदि और केवल यदि प्रस्ताव के पक्ष में सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा डाले गए मत इसके खिलाफ सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा डाले गए मतों की संख्या के कम से कम दो गुना होते हों।

- (ग) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तावित असूचीबद्धता के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए संबद्ध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन करेगी; और

- (घ) विशेष संकल्प पारित करने के एक वर्ष के भीतर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में संबद्ध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को अंतिम आवेदन करेगी :

परंतु यह कि खण्ड (ख) में यथा निर्दिष्ट विशेष संकल्प के अनुसरण में, इन विनियमों के प्रारंभ के पूर्व पारित, अंतिम आवेदन विशेष संकल्प के पारित किये जाने की तारीख से एक वर्ष या इन विनियमों के प्रारंभ से छह मास की कालावधि के भीतर, जो भी पश्चात्पूर्वी हो, किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन असूचीबद्धता के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन चाहने वाले आवेदन के साथ असूचीबद्ध किये जाने के लिए चाहे गये इक्विटी शेयरों की बाबत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 के विनियम 55क के अधीन यथा अपेक्षित लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न की जाएगी, आवेदन की तारीख से पूर्व छह मास की कालावधि का समावेश करते हुए।

(3) असूचीबद्धता के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन चाहने वाले आवेदन को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, सभी प्रकार से पूर्ण ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस कार्य दिवसों से अनधिक कालावधि के भीतर निपटाया जाएगा।

(4) असूचीबद्धता के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन चाहने वाले आवेदन पर विचार करते समय, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज नावाजिब

रूप से ऐसे आवेदन को नहीं रोकेंगे, किन्तु निम्नलिखित के विषय में कंपनी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि यह इसका समाधान करे —

- (क) उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) का अनुपालन;
- (ख) कंपनी द्वारा विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायतों को दूर करना;
- (ग) उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को सूचीबद्धता फीस का भुगतान;
- (घ) उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार की किसी शर्त का अनुपालन जो इसके इक्विटी शेयरधारकों के हितों से तात्त्विक रूप से संबंधित हो;
- (ङ) प्रतिभूति बाजार में इसके क्रियाकलापों के संबंध में कंपनी को खिलाफ लंबित कोई मुकदमा या कार्रवाई या कोई अन्य मामला जो इसके इक्विटी शेयरधारकों के हितों से तात्त्विक रूप से संबंधित हो;
- (च) कोई अन्य सुसंगत मामला जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सत्यापन करने के लिए ठीक समझे।

(5) उप-विनियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन किये गये असूचीबद्धता के लिए अंतिम आवेदन के साथ अध्याय IV के उपबंधों के अनुसार निकास अवसर दिये जाने का ऐसा सबूत संलग्न किया जाएगा, जैसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अपेक्षा करे।

अध्याय IV

निकास अवसर

9. अध्याय IV का लागू होना. — इस अध्याय के उपबंध विनियम 5 के अधीन या विनियम 6 के खण्ड (ख) के अधीन किए जाने के लिए चाही गई किसी असूचीबद्धता के प्रति लागू होंगे।

10. सार्वजनिक घोषणा. — (1) कंपनी के संप्रवर्तक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्धता के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की प्राप्ति पर, व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक, व्यापक परिचालन वाले एक हिन्दी राष्ट्रीय दैनिक और उस प्रदेश के प्रादेशिक भाषा के एक समाचारपत्र में सार्वजनिक घोषणा करेंगे जहाँ संबद्ध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है।

(2) सार्वजनिक घोषणा में समस्त तात्त्विक जानकारी अंतर्विष्ट होगी जिसमें अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट जानकारी सम्मिलित है और जिसमें कोई मिथ्या या भ्रामक कथन अंतर्विष्ट नहीं होगा।

(3) सार्वजनिक घोषणा एक तारीख, जो सार्वजनिक घोषणा की तारीख से तीस कार्य दिवसों के अपश्चात् का दिन हो, को भी विनिर्दिष्ट करेगी, जो उन शेयरधारकों के नामों को अवधारित करने के लिए "विनिर्दिष्ट तारीख" होगी जिनको प्रस्ताव-पत्र भेजा जाएगा।

(4) सार्वजनिक घोषणा करने से पूर्व, संप्रवर्तक बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत मर्चेंट बैंककार और ऐसे अन्य मध्यवर्तियों को नियुक्त करेगा जो आवश्यक समझे जायें।

(5) इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संप्रवर्तक और मर्चेंट बैंककार की होगी।

(6) कोई भी संप्रवर्तक उप-विनियम (4) के अधीन मर्चेंट बैंककार के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा यदि ऐसा व्यक्ति संप्रवर्तक का सहयुक्त है।

11. निलंब खाता. — (1) विनियम 10 के अधीन सार्वजनिक घोषणा करने से पूर्व, संप्रवर्तक निलंब खाता खोलेगा और उसमें सार्वजनिक शेयरधारकों के पास बकाया इक्विटी शेयरों के निम्नतम मूल्य तथा संख्या के आधार पर परिकलित प्रतिफल की कुल प्राक्कलित रकम को जमा करेगा।

(2) अंतिम कीमत के अवधारण और अंतिम कीमत को स्वीकार करते हुए विनियम 18 के अधीन सार्वजनिक घोषणा करने पर, संप्रवर्तक तुरंत निलंब खाते में ऐसी अतिरिक्त राशि जमा करेगा जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास बकाया इक्विटी शेयरों की बाबत प्रतिफल के रूप में देय तथा सदेय पूर्ण राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

(3) निलंब खाता या तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास जमा नकदी, या मर्चेंट बैंककार के पक्ष में बैंक गारंटी, या दोनों के संयोजन के रूप में होगा।

(4) जहां निलंब खाता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास जमा के रूप में होता है तो वहां संप्रवर्तक, खाता खोलते समय, निलंब खाते की जमा में पड़ी रकम के लिए बैंकर चैकों या मांगदेय ड्राफ्टों को जारी करने हेतु बैंक को अनुदेश देने के लिए मर्चेंट बैंककार को सशक्त करेगा, इन विनियमों में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, और ऐसी जमा रकम, यदि कोई हो, प्रस्ताव में निविदत तथा विनियम 21 के उप-विनियम (1) के अधीन निविदत इक्विटी शेयरों के लिए प्रतिफल के पूर्ण भुगतान के पश्चात् शेष, को संप्रवर्तक को निर्मुक्त किया जाएगा।

(5) जहां निलंब खाता बैंक गारंटी के रूप में होता है, तो वहां ऐसी बैंक गारंटी तब तक विद्यमान होगी जब तक विनियम 21 के उप-विनियम (1) के अधीन निविदत सभी शेयरों की बाबत भुगतान किए जाते हैं।

12. प्रस्ताव-पत्र. — (1) संप्रवर्तक इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक शेयरधारकों को प्रस्ताव-पत्र प्रेषित करेगा, सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पैंतालीस कार्य दिवसों के अपश्चात्, ताकि बोली की कालावधि के खुलने से कम से कम पांच कार्य दिवसों के पूर्व उनके पास पहुंच सकें।

(2) प्रस्ताव-पत्र असूचीबद्ध किए जाने के लिए चाहे गए वर्ग के इक्विटी शेयरों को धारण करने वाले सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजे जाएंगे जिनके नाम विनियम 10 के उप-नियम (3) के अधीन सार्वजनिक घोषणा में विनिर्दिष्ट तारीख को कम्पनी या निक्षेपागार के रजिस्टर पर उपस्थित हों।

(3) सार्वजनिक घोषणा में किए गए सभी प्रकटीकरण और ऐसे अन्य प्रकटीकरण प्रस्ताव पत्र में अंतर्विष्ट होंगे जो सोच-समझकर विनिश्चय करने में शेयरधारकों के लिए आवश्यक हों।

(4) प्रस्ताव पत्र के साथ सार्वजनिक शेयरधारकों के उपयोग के लिए बोली-फार्म और विनियम 21 के उप-विनियम (1) के अधीन शेयरों को निविदा करने के लिए उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला फार्म संलग्न किया जाएगा।

13. बोली की कालावधि.—(1) प्रस्ताव के खुलने की तारीख सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पचपन कार्य दिवसों से पश्चात् की नहीं होगी।

(2) प्रस्ताव तीन कार्य दिवसों की न्यूनतम कालावधि और पांच कार्य दिवसों की अधिकतम कालावधि के लिए खुला रहेगा, जिसके दौरान सार्वजनिक शेयरधारक अपनी बोलियां निविदा कर सकेंगे।

14. बही-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शेयर-धारकों का अधिकार.—(1) इक्विटी शेयरों, जिनकी असूचीबद्धता चाही जाती है, के सभी सार्वजनिक शेयरधारक अनुसूची II में विनिर्दिष्ट रीति में बही-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार होंगे।

(2) संप्रवर्तक या किन्हीं संप्रवर्तकों के साथ सामान्य मति से कार्य करता हुआ व्यक्ति प्रस्ताव में बोली नहीं लगाएगा और मर्चेट बैंककार इस उप-विनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(3) अभिरक्षक द्वारा धारित अंडरलाइंग शेयरों के आधार पर जारी निक्षेपागार रसीदों का कोई धारक और कोई ऐसा अभिरक्षक प्रस्ताव में भाग लेने का हकदार नहीं होगा।

(4) उप-विनियम (3) में अंतर्विष्ट कोई भी बात निक्षेपागार रसीदों के किसी धारक के उप-विनियम (1) के अधीन बही-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी यदि निक्षेपागार रसीदों का धारक ऐसी निक्षेपागार रसीदों का विनियम उस वर्ग के शेयरों से करता है जो असूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं।

15. प्रस्ताव कीमत.—(1) प्रस्ताव कीमत का अवधारण अनुसूची II में विनिर्दिष्ट रीति में बही-निर्माण के माध्यम से किया जाएगा, उप-विनियम (2) के अधीन निम्नतम मूल्य को नियत करने और सार्वजनिक घोषणा तथा प्रस्ताव-पत्र में उसके प्रकटीकरण के पश्चात्।

(2) निम्नतम मूल्य निम्नलिखित से कम नहीं होगा,—

(क) जहां इक्विटी शेयरों का व्यापार उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में बारंबार होता है जहां वे सूचीबद्ध हैं, उस तारीख से पूर्ववर्ती छब्बीस सप्ताहों या दो सप्ताहों के दौरान कम्पनी के इक्विटी शेयरों के अंतिम मूल्यों के साप्ताहिक उच्च तथा निम्न का औसत, जिसको मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को उस बोर्ड बैठक की सूचना दी गई थी जिसमें असूचीबद्ध के प्रस्ताव पर विचार हुआ था, जो भी उच्चतर है, उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में यथा उक्तथित जहां कम्पनी के इक्विटी शेयरों का व्यापार अति बारंबार होता है;

(ख) जहां कम्पनी के इक्विटी शेयरों का व्यापार उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में बारंबार नहीं होता है जहां वे सूचीबद्ध हैं, उप-विनियम (3) के उपबंधों के अनुसार अवधारित निम्नतम मूल्य; या

(ग) जहां इक्विटी शेयरों का व्यापार कुछ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में बारंबार होता है और कुछ अन्य मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में बारंबार नहीं होता है जहां वे सूचीबद्ध हैं, उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसार निकाले गए मूल्यों का उच्चतम।

स्पष्टीकरण : इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, इक्विटी शेयरों को बारंबार व्यापारित नहीं समझा जाएगा, यदि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में, उस मास के पूर्विक पूर्ववर्ती छह कलेंडर मास के दौरान ऐसे शेयरों में वार्षिक व्यापारिक व्यापारावर्त जिसमें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को उस बोर्ड बैठक की सूचना दी गई थी जिसमें असूचीबद्धता के प्रस्ताव पर विचार हुआ था, उस वर्ग के कुल सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के पाँच प्रतिशत (इक्विटी शेयरों की संख्या द्वारा) से कम है और पद बारंबार व्यापारित होने का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, निम्नतम मूल्य का अवधारण संप्रवर्तक और मर्चेट बैंककार द्वारा निम्नलिखित कारकों पर विचार करते हुए किया जाएगा :

(क) असूचीबद्ध किए जाने के लिए चाहे गये उस वर्ग के इक्विटी शेयरों के अर्जनों, यदि कोई हों, के लिए संप्रवर्तक द्वारा अदा की गई उच्चतम कीमत, जिसमें सार्वजनिक या साधिकार (राइट्स) निर्गम में आबंटन या अधिमानी आबंटन के रूप में सम्मिलित है, उस तारीख के पूर्व छब्बीस सप्ताहों की कालावधि के दौरान जिसको मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को उस बोर्ड बैठक की सूचना दी गई थी जिसमें असूचीबद्धता के प्रस्ताव पर विचार हुआ था और उस तारीख के पश्चात् सार्वजनिक घोषणा की तारीख तक; और

(ख) अन्य मानदंड जिनमें शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर प्रतिफल, कम्पनी के शेयरों का बही मूल्य, उपार्जन प्रति शेयर, उद्योग के औसत के मुकाबले में कीमत उपार्जन गुणक सम्मिलित हैं।

16. प्रस्ताव कीमत को स्वीकार न करने का संप्रवर्तक का अधिकार.—(1) संप्रवर्तक बही-निर्माण प्रक्रिया द्वारा अवधारित प्रस्ताव कीमत पर इक्विटी शेयरों को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं होगा।

(2) जहां संप्रवर्तक इस प्रकार अवधारित प्रस्ताव कीमत को स्वीकार न करने का विनिश्चय करता है,—

(क) संप्रवर्तक प्रस्ताव के अनुसरण में निविदा किन्हीं इक्विटी शेयरों को अर्जित नहीं करेगा और अनुसूची II के पैरा 7 या 9 के अनुसरण में शेयरधारक द्वारा जमा किए गए या गिरवी रखे गए इक्विटी शेयर बोली की कालावधि के समाप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर उसको लौटाये या निर्मुक्त किए जाएंगे;

(ख) कम्पनी इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता के लिए एक्सचेंज को अंतिम आवेदन नहीं करेगी;

(ग) संप्रवर्तक विनियम 11 के अधीन खोले गए निलम्ब खाते को बंद कर सकेगा; और

(घ) उस मामले में जहाँ बोली की कालावधि के खुलने पर सार्वजनिक शेयरधारिता सूचीबद्धता करार के अधीन अपेक्षित सार्वजनिक शेयरधारिता के न्यूनतम स्तर से कम थी, संप्रवर्तक यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक शेयरधारिता उप-विनियम (3) में उल्लिखित किन्हीं रीतियों के माध्यम से बोली के समाप्त होने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर ऐसे न्यूनतम स्तर तक लायी जाएगी।

(3) उप-विनियम (2) के खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, सार्वजनिक शेयरधारिता को निम्नलिखित रीतियों में से किसी रीति द्वारा बढ़ाया जा सकेगा :

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 और प्रतिभूतियों के निर्गमन तथा प्रकटीकरणों से संबंधित बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों या विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए कम्पनी द्वारा नये शेयरों के निर्गमन द्वारा;

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 और प्रतिभूतियों के निर्गमन तथा प्रकटीकरणों से संबंधित बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों या विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए अपनी धारिताओं के विक्रय के लिए प्रस्ताव करते हुए संप्रवर्तक द्वारा; या

(ग) पारदर्शी रीति में द्वितीयक बाजार के माध्यम से अपनी धारिताओं का विक्रय करते हुए संप्रवर्तक द्वारा।

17. अर्जित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की न्यूनतम संख्या.—अध्याय III के अधीन किया गया प्रस्ताव सफल समझा जाएगा यदि प्रस्ताव के पश्चात्, संप्रवर्तक (सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों के साथ) की शेयरधारिता, अनुसूची II के अनुसार अवधारित अंतिम कीमत पर पात्र बोलियों के माध्यम से स्वीकृत शेयरों के साथ, निम्नलिखित के उच्चतर तक पहुंच जाती है—

(क) उस वर्ग के कुल निर्गमित शेयरों का नब्बे प्रतिशत, उन शेयरों को अपवर्जित करते हुए जो अभिरक्षक द्वारा धारित हैं और जिनके प्रति निक्षेपागार रसीदें विदेश में जारी की गयी हैं; या

(ख) प्रस्ताव-पूर्व संप्रवर्तक शेयरधारिता (उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों के साथ) का कुल प्रतिशत और प्रस्ताव के आकार का पचास प्रतिशत।

18. प्रस्ताव के बंद होने के पश्चात् प्रक्रिया.—प्रस्ताव के बंद होने के आठ कार्य दिवसों के भीतर, संप्रवर्तक और मर्चेंट बैंकर उन सभी समाचार पत्रों में निम्नलिखित के संबंध में सार्वजनिक घोषणा

करेगा जिनमें विनियम 10 के उप-विनियम (1) के अधीन सार्वजनिक घोषणा की गयी थी :-

(i) विनियम 17 के निबंधनों के अनुसार प्रस्ताव की सफलता, अर्जनकर्ता द्वारा स्वीकृत अंतिम कीमत के साथ; या

(ii) विनियम 19 के निबंधनों के अनुसार प्रस्ताव की असफलता; या

(iii) अनुसूची II के अधीन निर्धारित अंतिम कीमत की विनियम 16 के अधीन नामजुरी, संप्रवर्तकों द्वारा।

19. प्रस्ताव की असफलता.—(1) जहाँ प्रस्ताव विनियम 16 के अधीन नामजुर किया जाता है या विनियम 17 के अनुसार सफल नहीं है, तो वहाँ प्रस्ताव को असफल हुआ समझा जाएगा और कोई इक्विटी शेयर ऐसे प्रस्ताव के अनुसरण में अर्जित नहीं किए जाएंगे।

(2) जहाँ प्रस्ताव असफल रहता है—

(क) अनुसूची II के पैरा 7 या 9 के अधीन शेयरधारक द्वारा जमा किए गए या गिरवी रखे गए इक्विटी शेयर बोली की कालावधि की समाप्ति से दस कार्य दिवसों के भीतर उसको लौटाए या निर्मुक्त किए जाएंगे;

(ख) कोई भी अंतिम आवेदन इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता के लिए एक्सचेंज को नहीं किया जाएगा; और

(ग) विनियम 11 के अधीन खोला गया निलम्ब खाता बंद किया जाएगा।

20. प्रतिफल का भुगतान और इक्विटी शेयरों को लौटाना.—(1) संप्रवर्तक प्रस्ताव की सफलता को अभिनिश्चित करने पर तुरंत, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत निर्गमन बैंकर के पास एक विशेष खाता खोलेगा और उसमें, प्रस्ताव में निविदत्त इक्विटी शेयरों की बाबत प्रतिफल के रूप में देय तथा संदेय पूर्ण रकम को अंतरित करेगा, निलम्ब खाते से।

(2) सभी शेयरधारकों जिनके इक्विटी शेयरों की वास्तविकता सत्यापित हो जाती है को प्रस्ताव के बंद होने से दस कार्य दिवसों के भीतर सार्वजनिक घोषणा में कथित अंतिम कीमत अदा की जाएगी।

(3) अनुसूची II के पैरा 7 या 9 के अनुसरण में शेयरधारक द्वारा जमा किए गए या गिरवी रखे गए इक्विटी शेयर उसको लौटाए जाएंगे या निर्मुक्त किए जाएंगे, प्रस्ताव के बंद होने से दस कार्य दिवसों के भीतर, उन मामलों में जहाँ उनसे संबंधित बोलियों को स्वीकार नहीं किया गया है।

21. इक्विटी शेयरों को निविदत्त करने के लिए शेष शेयरधारकों का अधिकार.—(1) जहाँ, इन विनियमों के निबंधनों के अनुसार निविदत्त इक्विटी शेयरों को स्वीकार किए जाने के अनुसरण में, इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हो जाते हैं, ऐसे इक्विटी शेयरों को धारण करने वाला कोई शेष सार्वजनिक शेयरधारक अपने शेयर संप्रवर्तक को असूचीबद्धता की तारीख से कम से कम एक वर्ष की

कालावधि तक निविदत्त कर सकेगा और, ऐसे मामले में, संप्रवर्तक निविदत्त शेयरों को उसी अंतिम कीमत पर स्वीकार करेगा जिस पर शेयरों की पूर्वतर स्वीकृति दी गयी थी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन स्वीकार किए गए शेयरों के लिए प्रतिफल का भुगतान निलम्ब खाते में पड़ी बाकी रकम में से किया जाएगा।

(3) निलम्ब खाते में रकम या बैंक गारंटी संप्रवर्तक को निर्मुक्त नहीं की जाएगी जब तक कि सभी भुगतान उप-विनियम (1) के अधीन निविदत्त शेयरों की बाबत नहीं कर दिये जाते।

अध्याय V

अनिवार्य असूचीबद्धता

22. स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनिवार्य असूचीबद्धता.—(1) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, आदेश द्वारा, प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क के अधीन बनाये गये नियमों में विहित किसी आधार पर कम्पनी के किन्हीं इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध कर सकेगा;

परंतु यह कि कोई भी आदेश इस उप-विनियम के अधीन नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबद्ध कंपनी को सुने जाने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(2) अनिवार्य असूचीबद्धता के संबंध में विनिश्चय मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा गठित किये जाने वाले पैनल द्वारा किया जायेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

- (क) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के दो निदेशक (जिनमें से एक सार्वजनिक प्रतिनिधि होगा);
- (ख) विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) का एक प्रतिनिधि;
- (ग) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या कम्पनी रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि; और
- (घ) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का कार्यपालक निदेशक या सचिव।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन आदेश देने से पूर्व, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक और उस प्रदेश के प्रादेशिक भाषा के एक समाचार-पत्र में सूचना देगा जहाँ संबद्ध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, प्रस्तावित असूचीबद्धता की, सूचना से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवसों की समय कालावधि देते हुए, जिसके भीतर अभ्यावेदन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जा सकेंगे जो प्रस्तावित असूचीबद्धता द्वारा व्यथित हो और ऐसी सूचना को अपनी व्यापारिक प्रणालियों तथा वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा।

(4) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उप-विनियम (1) के अधीन कोई आदेश पारित करते समय, अभ्यावेदनों पर विचार करेगा, यदि कोई हों, कम्पनी द्वारा किये गये और उप-विनियम (3) के अधीन दी गई सूचना के जवाब में प्राप्त किन्हीं अभ्यावेदनों पर भी और अनुसूची III में विनिर्दिष्ट मानदंड का अनुपालन करेगा।

(5) अध्याय IV के उपबंध इस अध्याय के अधीन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गयी अनिवार्य असूचीबद्धता के प्रति लागू नहीं होंगे।

(6) जहाँ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उप-विनियम (1) के अधीन आदेश पारित करता है, वहाँ यह,—

(क) व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक और उस प्रदेश के प्रादेशिक भाषा के एक समाचार-पत्र में तुरंत सूचना प्रकाशित करेगा जहाँ संबद्ध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, ऐसी असूचीबद्धता के तथ्य की, उसमें कम्पनी के नाम तथा पते को, विनियम 23 के उप-विनियम (1) के अधीन अवधारित असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य को और कम्पनी के उन संप्रवर्तकों के नामों तथा पतों को प्रकट करते हुए जो विनियम 23 के उप-विनियम (3) के अधीन दायी होंगे; और

(ख) सभी अन्य स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करेगा जहाँ कम्पनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, ऐसी असूचीबद्धता और आस-पास की परिस्थितियों के बारे में।

23. अनिवार्य असूचीबद्धता के मामले में सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार.—(1) जहाँ कम्पनी के इक्विटी शेयर इस अध्याय के अधीन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीबद्ध किये जाते हैं, वहाँ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्वतंत्र मूल्यांकक या मूल्यांककों को नियुक्त करेगा जो असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य को अवधारित करेंगे।

(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विशेषज्ञ मूल्यांककों का पैनल बनायेगा जिनमें से मूल्यांकक या मूल्यांककों को उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(3) कम्पनी का संप्रवर्तक सार्वजनिक शेयरधारकों से असूचीबद्ध इक्विटी शेयर मूल्यांकक द्वारा अवधारित मूल्य उन्हें अदा करते हुए अर्जित करेगा, उनके शेयरों को रखे रहने के उनके विकल्प के अधीन।

स्पष्टीकरण : उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "मूल्यांकक" से चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थ के भीतर चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, जिसका उस अधिनियम के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थान द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समकक्षी पुनर्विलोकन किया गया है, अथवा असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्य अवधारित करने के लिए नियुक्त मर्चेंट बैंकिंग अभिप्रेत है;

(ख) असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्य मूल्यांकक द्वारा विनियम 15 में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाएगा।

24. अनिवार्य असूचीबद्धता के परिणाम.—जहाँ कम्पनी को इस अध्याय के अधीन अनिवार्यतः असूचीबद्ध किया गया हो, तो वहाँ कम्पनी, इसके पूर्णकालिक निदेशक, इसके संप्रवर्तक तथा

कम्पनियाँ जो उनमें से किसी द्वारा संप्रवर्तित हैं प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसी असूचीबद्धता की तारीख से दस वर्षों की कालावधि के लिए प्रतिभूति बाजार में पहुँच नहीं रखेगी या किन्हीं इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता नहीं चाहेगी।

अध्याय VI

बोर्ड की शक्तियाँ

25. स्पष्टीकरण जारी करने की बोर्ड की शक्ति.—इन विनियमों के लागू होने या निर्वचन में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा।

26. बोर्ड द्वारा निदेश.—अधिनियम के उपबंधों और प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड इन विनियमों के किसी अतिक्रमण के मामले में और विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) तथा प्रतिभूति बाजार के हितों में ऐसे निदेश दे सकेगा जो यह ठीक समझे :

परंतु यह कि बोर्ड, या तो ऐसे आदेशों को पारित करने से पूर्व या के पश्चात्, संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा।

अध्याय VII

छोटी कम्पनियों के लिए विशेष उपबंध और विधि की क्रिया से असूचीबद्धता

27. छोटी कम्पनियों के मामले में विशेष उपबंध.—(1) जहाँ कम्पनी की समादत्त पूँजी एक करोड़ रुपये तक है और इसके इक्विटी शेयर विनिश्चय की तारीख से ठीक पहले एक वर्ष में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापारित नहीं हुए थे, ऐसे इक्विटी शेयरों को उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्ध किया जा सकेगा जहाँ वे सूचीबद्ध हैं, अध्याय IV में प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना।

(2) जहाँ कम्पनी के पास तीन सौ या कम सार्वजनिक शेयरधारक हैं और जहाँ ऐसी कम्पनी में ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का समादत्त मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, इसके इक्विटी शेयरों को उन सभी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से असूचीबद्ध किया जा सकेगा जहाँ वे सूचीबद्ध हैं, अध्याय IV में प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना।

(3) इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अधीन की जा सकेगी केवल यदि, विनियम 8 की अपेक्षाओं को पूरा किये जाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है :—

(क) संप्रवर्तक मर्चेंट बैंककार को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से विकास कीमत को विनिश्चित करता है;

(ख) सार्वजनिक शेयरधारकों को प्रस्तावित विकास कीमत मर्चेंट बैंककार के परामर्श से निकली गई कीमत से कम नहीं होगी ;

(ग) संप्रवर्तक कम्पनी में सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को अलग-अलग से लिखता है, इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध कराने के अपने आशय की उन्हें सूचना

देते हुए, विकास कीमत को उसके लिए न्यायोचित्य के साथ उपदर्शित करते हुए और असूचीबद्धता हेतु प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगते हुए;

(घ) कम से कम ऐसे नब्बे प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारक असूचीबद्धता के लिए प्रस्ताव के प्रति लिखित रूप में अपनी निश्चयात्मक सहमति देते हैं और उन्होंने या तो संप्रवर्तक द्वारा प्रस्तावित कीमत पर अपने इक्विटी शेयरों को बेचने की या इक्विटी शेयरों के धारक बने रहने की सहमति दी है भले ही वे असूचीबद्ध हो जाते हैं;

(ङ) संप्रवर्तक खंड (ग) के अधीन दी गयी पहली संसूचना के पचहत्तर कार्य दिवसों के भीतर इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता के लिए निश्चयात्मक सहमति को आमंत्रित करने तथा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया को पूरा करता है;

(च) संप्रवर्तक खंड (ङ) में नियत पचहत्तर कार्य दिवसों की समाप्ति की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर नकद रूप में प्रतिफल की अदायगी करता है।

(4) उप-विनियम (3) के खंड (ग) के अधीन सार्वजनिक शेयरधारकों को दी गई संसूचना में, विनियम 15 में उल्लिखित लागू मानदंडों के विशिष्ट संदर्भ में प्रस्ताव कीमत के लिए न्यायोचित्य अंतर्विष्ट होगा और विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख होगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में बही निर्माण पद्धति के माध्यम से विकास कीमत के निर्धारण से अभिमुक्ति देने के लिए सहमति सम्मिलित होगी।

(5) संबद्ध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इस विनियम के अनुपालन से स्वयं का समाधान हो जाने पर ऐसे इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध कर सकेगा।

28. परिसमापन, मान्यता वापस लिये जाने, आदि के मामले में असूचीबद्धता.—(1) कम्पनी जिसके इक्विटी शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं की परिसमापन कार्यवाहियों के मामले में, ऐसी कम्पनी के शेयरधारकों के अधिकार, यदि कोई हों, उन कार्यवाहियों के प्रति लागू विधियों के अनुसार होंगे।

(2) जहाँ बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान की गयी मान्यता वापस ले लेता है या इसको मान्यता के नवीकरण से इन्कार करता है, तो वहाँ बोर्ड, विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में उस एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनियों के इक्विटी शेयरों की प्रास्थिति की बाबत समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

अध्याय VIII

विविध

29. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज—अनुपालन का अनुश्रवण करना.—संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे और के अनुपालन का अनुश्रवण करेंगे और बोर्ड को अननुपालन किसी दृष्टांत की रिपोर्ट देंगे जो उनकी सूचना में आता हो।

30. असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता,—

(1) सूचीबद्धता के लिए कोई भी आवेदन किन्हीं इक्विटी शेयरों की बाबत नहीं किया जाएगा :

(क) जिन्हें अध्याय III के अधीन या अध्याय VII के अधीन (विनियम 27 के सिवाय) असूचीबद्ध किया गया है, असूचीबद्धता से पांच वर्षों की कालावधि के लिए;

(ख) जिन्हें अध्याय V के अधीन असूचीबद्ध किया गया है, असूचीबद्धता से दस वर्षों की कालावधि के लिए ।

(2) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, असूचीबद्धता इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया जा सकेगा जहां इस संबंध में सिफारिश रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा की गयी है ।

(3) किन्हीं इक्विटी शेयरों जिन्हें असूचीबद्ध किया गया था कि सूचीबद्धता के लिए आवेदन पर विचार करते समय, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उन तथ्यों और परिस्थितियों का सम्यक् ध्यान रखेगा जिनके अधीन असूचीबद्धता की गयी थी ।

(4) असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बाबत किया गया सूचीबद्धता के लिए आवेदन ऐसे इक्विटी शेयरों की नयी सूचीबद्धता के लिए किया गया आवेदन समझा जाएगा और कम्पनियों जो सूचीबद्ध नहीं हैं के इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता से संबंधित विधि के उपबंधों के अध्याधीन होगा ।

31. संक्रमणकालीन उपबंध.—(1) इन विनियमों के प्रारम्भ से पूर्व भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता) मार्गदर्शक सिद्धांत, 2003 के अधीन कोई बात जो की गई या जिसके किए जाने का लोप किया गया अथवा अर्जित या प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनियमित होंगे ।

(2) किसी कम्पनी या किसी संप्रवर्तक या अर्जनकर्ता जिसने कम्पनी की प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता चाही द्वारा किये गये असूचीबद्धता के लिए किसी आवेदन, इन विनियमों के प्रारम्भ से पूर्व और ऐसे प्रारम्भ की तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पास लंबित, पर कार्यवाही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता) मार्गदर्शक सिद्धांत, 2003 के अधीन की जाएगी ।

(3) इन विनियमों के प्रारम्भ से पूर्व भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता) मार्गदर्शक सिद्धांत, 2003 के अधीन पहले ही से पूर्ण विकास अवसर या आरम्भ किए गए किन्तु अपूर्ण विकास अवसर की बाबत शेष प्रक्रियाओं को, पूरा किया जाएगा और उसके अनुसरण में किए गए असूचीबद्धता के लिए आवेदन पर कार्यवाही उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन की जाएगी ।

अनुसूची I**[विनियम 10 (2) देखें]****सार्वजनिक घोषणा की विषय-वस्तु**

1. निम्नतम मूल्य और प्रस्ताव कीमत और कैसे वे निकाली गई ।
2. प्रस्ताव के खुलने और बंद होने की तारीखें ।
3. एक्सचेंज का नाम जिससे इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता चाही जाती है ।
4. वह रीति जिसमें प्रस्ताव को शेयर धारकों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है ।
5. प्रस्ताव की सफलता के लिए न्यूनतम स्वीकृति शर्त संबंधी प्रकटीकरण ।
6. मजैट बैंकर और अन्य मध्यवर्तियों के नाम, शेयरधारकों के लिए हेल्पलाइन नम्बर के साथ ।
7. विनियम 10 के उप-विनियम (3) के अनुसार नियत विनिर्दिष्ट तारीख ।
8. प्रस्तावित असूचीबद्धता का उद्देश्य ।
9. प्रस्ताव के खुलने से लेकर प्रतिफल के पुगतान या इक्विटी शेयरों को लौटाये जाने तक की प्रस्तावित समय-सारणी ।
10. निलम्ब खाते और उसमें जमा रकम के ब्यौरे ।
11. सूचीबद्धता के ब्यौरे और स्टॉक बाजार के आंकड़े :
(क) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान कम्पनी के इक्विटी शेयरों की उच्च, निम्न तथा औसत बाजार कीमतें ;
(ख) सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पूर्ववर्ती छह मास के लिए मासिक उच्च तथा निम्न कीमतें; और
(ग) सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पूर्ववर्ती छह मास के दौरान प्रत्येक मास में व्यापारित इक्विटी शेयरों की मात्रा ।
12. वर्तमान पूंजी की संरचना और शेयरधारिता स्वरूप ।
13. असूचीबद्धता के बाद का संभाव्य शेयरधारिता स्वरूप ।
14. सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों के साथ संप्रवर्तक की और जहां संप्रवर्तक कम्पनी है वहां संप्रवर्तक के निदेशकों की और जो व्यक्ति कम्पनी के नियंत्रण में हैं उन व्यक्तियों की कुल शेयरधारिता ।
15. सार्वजनिक घोषणा की तारीख से ठीक पहले पांच वर्षों के दौरान किए गए प्रतिभूतियों के निर्गमों की आगमों के उपयोग में, निर्गम के कथित उद्देश्य से, तात्त्विक विचलन, यदि कोई हो, को प्रकट करते हुए, कथन, जो कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा सत्य रूप में प्रमाणित किया जाना है ।

16. कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा यह पुष्टि करते हुए कथन कि वह समस्त तात्विक जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट कर दी गयी है जो सतत् सूचीबद्धता अपेक्षा के उपबंधों के अधीन प्रकट की जानी अपेक्षित है।

17. कम्पनी के अनुपालन अधिकारी का नाम।

18. इस पर संप्रवर्तक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और तारीख डाली जानी चाहिए। जहां संप्रवर्तक कम्पनी है, वहां सार्वजनिक घोषणा पर कम्पनी के निदेशक बोर्ड की ओर से इसके प्रबंधक या सचिव, यदि कोई हो, द्वारा और कम्पनी के कम से कम दो निदेशकों द्वारा, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा जहां वह है, तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अनुसूची II

[विनियम 15 (1) देखें]

बही-निर्माण प्रक्रिया

1. बही-निर्माण प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबद्ध पारदर्शी सुविधा के माध्यम से की जाएगी और संप्रवर्तक इस प्रयोजन के लिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ करार करेगा।
2. सार्वजनिक घोषणा और प्रस्ताव पत्र पैरा 1 में उल्लिखित स्टॉक एक्सचेंज के पास अविलम्ब दाखिल किए जाएंगे और ऐसा स्टॉक एक्सचेंज तुरन्त उन्हें अपने वेबसाइट पर डालेगा।
3. बोली केंद्रों की न्यूनतम संख्या होगी :
(क) मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थित चार महानगर केंद्र;
(ख) उस प्रदेश में जिसमें कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है ऐसे नगर, जो पैरा 1 में उल्लिखित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट हैं।
4. सभी बोली केंद्रों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबद्ध कम्प्यूटर टर्मिनल होगा।
5. शेयरधारक बोली की कालावधि के समाप्त होने से पूर्व एक दिन के अपश्चात् अपनी बोलियों को वापस ले सकेंगे या उनका उर्ध्वमुखी पुनरीक्षण कर सकेंगे। बोलियों का अधोमुखी पुनरीक्षण अनुज्ञात नहीं होगा।
6. संप्रवर्तक बोली केंद्रों में "व्यापारिक सदस्यों" की नियुक्ति करेगा, जिनसे सार्वजनिक शेयरधारक ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर बोलियां डालने के लिए संपर्क कर सकेंगे।
7. विकास अवसर का उपभोग करने की इच्छा रखने वाले गैर-कागजी (डिमैटीरियलाइज्ड) शेयर धारण करने वाले शेयरधारक इक्विटी शेयरों को जिनकी बाबत बोलियां लगायी जाती हैं, आदेश डाले जाने के पूर्व इस प्रयोजन के लिए मर्चेन्ट बैंककार द्वारा खोले गए विशेष निक्षेपागार खाते में जमा कर सकेंगे या, आनुकूलिक रूप से उक्त खाते के पक्ष में

मर्चेन्ट बैंककार के प्रति उसके लिए गिरवी चिन्हांकित कर सकेंगे।

8. मर्चेन्ट बैंककार यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त विशेष निक्षेपागार खाते में इक्विटी शेयर संप्रवर्तक के खाते में अंतरित न हों जब तक कि उनकी बाबत बोलियां स्वीकार नहीं कर ली जातीं और भुगतान नहीं कर दिये जाते।
9. कागजी इक्विटी शेयरों के धारक अपने बोली के फार्म शेयर प्रमाणपत्र और अंतरण विलेख के साथ इस प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यापारिक सदस्य को भेज सकेंगे। जो प्रणाली में उनकी बोलियां दर्ज करने के ठीक पश्चात् उन्हें कम्पनी या शेयर अंतरण अभिकर्ता को उनकी वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए भेजेंगे। कम्पनी या शेयर अंतरण अभिकर्ता प्रमाणपत्र जो वास्तविक पाये जाते हैं मर्चेन्ट बैंककार को परिदत्त करेंगे, जो इन्हें तब तक संप्रवर्तक के हवाले नहीं करेगा जब तक कि उसकी बाबत बोलियां स्वीकार नहीं कर ली जातीं और भुगतान नहीं कर दिये जाते। उन प्रमाणपत्रों की बाबत बोलियां प्रणाली से हटा दी जाएंगी जो वास्तविक नहीं पाये जाते हैं।
10. कागजी प्रमाणपत्रों का सत्यापन विनियम 18 के अधीन सार्वजनिक घोषणा करने के लिए समय पर पूरा किया जाएगा।
11. प्रणाली में डाली गई बोलियों के लिए लेखापरीक्षा-खाका होगा जिनमें स्टॉक दलाल के पहचान के व्यौर, समय मुहर तथा विशिष्ट आदेश संख्या सम्मिलित हैं।
12. अंतिम प्रस्ताव कीमत का अवधारण उस कीमत के रूप में किया जाएगा जिस पर इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा निविदत्त की जाती है। यदि अंतिम कीमत को स्वीकार कर लिया जाता है, तब, संप्रवर्तक सभी निविदत्त शेयरों को स्वीकार कर लेगा जहां लगायी गयी तत्संबंधी बोलियां अंतिम कीमत पर या उस कीमत पर हैं जो अंतिम कीमत से कम है। संप्रवर्तक यदि वह ठीक समझे उच्चतर अंतिम कीमत नियत कर सकेगा।

अनुसूची III

[विनियम 22(4) देखें]

अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए मानदंड

1. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उस कम्पनी के संप्रवर्तकों का पता लगाने के लिए सभी युक्तियुक्त कदम उठायेगा जिसके इक्विटी शेयर असूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, विनियम 23 के उप-विनियम (3) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से।

2. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कम्पनी के अधिकथित अनुपालन के स्वरूप तथा विस्तार पर और उन शेयरधारकों की संख्या तथा प्रतिशतता पर विचार करेगा जो ऐसे अनुपालन से प्रभावित हो सकेंगे।
3. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कम्पनी के अनुपालन की प्राप्ति को संबद्ध कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय से सत्यापित करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा।
4. कम्पनियों जिनके इक्विटी शेयर असूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं और उनके संप्रवर्तकों के नाम संक्षिप्त समय की कालावधि के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर पृथक खंड में प्रदर्शित किए जाएंगे। यदि असूचीबद्ध हों, तो नाम वेबसाइट पर एक अन्य पृथक खंड में अंतरित कर दिए जाएंगे।
5. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज समुचित मामलों में प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के सुसंगत उपबंधों के अधीन अधिकथित अनुपालनों के लिए कंपनी के पहचाने जा सकने वाले संप्रवर्तकों तथा निदेशकों के खिलाफ अभियोजन दाखिल करेगा।
6. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज समुचित मामलों में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 433 के अधीन कम्पनी का परिसमापन करने के लिए याचिका दाखिल करेगा या उक्त अधिनियम की धारा 560 के अधीन रजिस्ट्रार से कम्पनी का नाम काटे जाने के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार से अनुरोध करेगा।

के. एम. एब्रहाम, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/असल/69जेडबी/09]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th June, 2009

Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009

No. LAD-NRO/GN/2009-2010/09/165992.—In exercise of the powers conferred by Section 31, read with Section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), Section 30, sub-section (1) of Section 11 and sub-section (2) of Section 11A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (i) 'Act' means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
- (ii) 'Board' means the Securities and Exchange Board of India established under Section 3 of the Act;
- (iii) 'Company' means a company within the meaning of Section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and includes a body corporate of corporation established under a Central Act, State Act or Provincial Act for the time being in force, whose equity shares are listed on a recognised stock exchange;
- (iv) 'compulsory delisting' means delisting of equity shares of a company by a recognised stock exchange under Chapter V of these regulations;
- (v) 'public shareholders' means the holders of equity shares, other than the following :
 - (a) promoters;
 - (b) holders of depository receipts issued overseas against equity shares held with a custodian and such custodian;
- (vi) 'recognised stock exchange' means any stock exchange which has been granted recognition under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;
- (vii) 'Schedule' means a Schedule appended to these regulations;
- (viii) 'voluntary delisting' means delisting of equity shares of a company voluntarily on application of the company under Chapter III of these regulations;
- (ix) 'working days' means the working days of the Board.

(2) The words 'control', 'person acting in concert', 'promoter' and 'public shareholding' shall have the meanings respectively assigned to them under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 as amended from time to time.

(3) Words and expressions not defined in these regulations, but defined in or under the Act or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any statutory modification or re-enactment thereof, shall have the same meanings as in or under those enactments.

CHAPTER II

DELISTING OF EQUITY SHARES

3. Applicability.—(1) These regulations shall apply to delisting of equity shares of a company from

all or any of the recognised stock exchanges where such shares are listed.

(2) Nothing in these regulations shall apply to any delisting made pursuant to a scheme sanctioned by the Board for Industrial and Financial Reconstruction under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 or by the National Company Law Tribunal under section 424D of the Companies Act, 1956, if such scheme—

- (a) lays down any specific procedure to complete the delisting; or
- (b) provides an exit option to the existing public shareholders at a specified rate.

4. Delisting not permissible in certain circumstances and conditions for delisting.—(1) No company shall apply for and no recognised stock exchange shall permit delisting of equity shares of a company,—

- (a) pursuant to a buy back of equity shares by the company; or
- (b) pursuant to a preferential allotment made by the company; or
- (c) unless a period of three years has elapsed since the listing of that class of equity shares on any recognised stock exchange; or
- (d) if any instruments issued by the company, which are convertible into the same class of equity shares that are sought to be delisted, are outstanding.

(2) For the removal of doubts, it is clarified that no company shall apply for and no recognised stock exchange shall permit delisting of convertible securities.

(3) Nothing contained in clauses (c) and (d) of sub-regulation (1) shall apply to a delisting of equity shares falling under clause (a) of regulation 6.

(4) No promoter shall directly or indirectly employ the funds of the company to finance an exit opportunity provided under Chapter IV or an acquisition of shares made pursuant to sub-regulation (3) of regulation 23.

(5) No promoter or other person shall—

- (a) employ any device, scheme or artifice to defraud any shareholder or other person; or
- (b) engage in any transaction or practice that operates as a fraud or deceit upon any shareholder or other person; or
- (c) engage in any act or practice that is fraudulent, deceptive or manipulative—

in connection with any delisting sought or permitted or exit opportunity given or other acquisition of shares made under these regulations.

CHAPTER III

VOLUNTARY DELISTING

5. Delisting from all recognised stock exchanges.—Subject to the provisions of these regulations, a company may delist its equity shares from all the recognised stock exchanges where they are listed or from the only recognised stock exchange where they are listed :

Provided that all public shareholders holding equity shares of the class which are sought to be delisted are given an exit opportunity in accordance with Chapter IV.

6. Delisting from only some of the recognised stock exchanges.—A company may delist its equity shares from one or more recognised stock exchanges where they are listed and continue their listing on one or more other recognised stock exchanges, subject to the provisions of these regulations and subject to the following—

- (a) if after the proposed delisting from any one or more recognised stock exchanges, the equity shares would remain listed on any recognised stock exchange which has nationwide trading terminals, no exit opportunity needs to be given to the public shareholders; and
- (b) if after the proposed delisting, the equity shares would not remain listed on any recognised stock exchange having nationwide trading terminals, exit opportunity shall be given to all the public shareholders holding the equity shares sought to be delisted in accordance with Chapter IV.

Explanation : For the purposes of this regulation, 'recognised stock exchange having nation-wide trading terminals' means the Bombay Stock Exchange Limited, the National Stock Exchange of India Limited or any other recognised stock exchange which may be specified by the Board in this regard.

7. Procedure for delisting where no exit opportunity is required.—(1) In a case falling under clause (a) of regulation 6—

- (a) the proposed delisting shall be approved by a resolution of the board of directors of the company in its meeting;
- (b) the company shall give a public notice of the proposed delisting in at least one English national daily with wide circulation, one Hindi national daily with wide circulation and one regional language newspaper of the region where the concerned recognised stock exchanges are located;
- (c) the company shall make an application to the concerned recognised stock exchange for delisting its equity shares; and

- (d) the fact of delisting shall be disclosed in the first annual report of the company prepared after the delisting.

(2) The public notice made under clause (b) of sub-regulation (1) shall mention the names of the recognised stock exchanges from which the equity shares of the company are intended to be delisted, the reasons for such delisting and the fact of continuation of listing of equity shares on recognised stock exchange having nation-wide trading terminals.

(3) An application for delisting made under clause (c) of sub-regulation (1) shall be disposed of by the recognised stock exchange within a period not exceeding thirty working days from the date of receipt of such application complete in all respects.

8. Conditions and procedure for delisting where exit opportunity is required.—(1) Any company desirous of delisting its equity shares under the provisions of Chapter III shall, except in a case falling under clause (a) of regulation 6,—

- (a) obtain the prior approval of the board of directors of the company in its meeting;
- (b) obtain the prior approval of shareholders of the company by special resolution passed through postal ballot, after disclosure of all material facts in the explanatory statement sent to the shareholders in relation to such resolution;

Provided that the special resolution shall be acted upon if and only if the votes cast by public shareholders in favour of the proposal amount to at least two times the number of votes cast by public shareholders against it.

- (c) make an application to the concerned recognised stock exchange for in-principle approval of the proposed delisting in the form specified by the recognised stock exchange; and
- (d) within one year of passing the special resolution, make the final application to the concerned recognised stock exchange in the form specified by the recognised stock exchange;

Provided that in pursuance of special resolution as referred to in clause (b), passed before the commencement of these regulations, final application shall be made within a period of one year from the date of passing of special resolution or six months from the commencement of these regulations, whichever is later.

(2) An application seeking in-principle approval for delisting under clause (c) of sub-regulation (1) shall be

accompanied by an audit report as required under regulation 55A of the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 in respect of the equity shares sought to be delisted, covering a period of six months prior to the date of the application.

(3) An application seeking in-principle approval for delisting shall be disposed of by the recognised stock exchange within a period not exceeding thirty working days from the date of receipt of such application complete in all respects.

(4) While considering an application seeking in-principle approval for delisting, the recognised stock exchange shall not unfairly withhold such application, but may require the company to satisfy it as to—

- (a) compliance with clause (b) of sub-regulation (1);
- (b) the resolution of investor grievances by the company; (c) payment of listing fees to that recognised stock exchange;
- (d) the compliance with any condition of the listing agreement with that recognised stock exchange having a material bearing on the interests of its equity shareholders;
- (e) any litigation or action pending against the company pertaining to its activities in the securities market or any other matter having a material bearing on the interests of its equity shareholders;
- (f) any other relevant matter as the exchange may deem fit to verify.

(5) A final application for delisting made under clause (d) of sub regulation (1) shall be accompanied with such proof of having given the exit opportunity in accordance with the provisions of Chapter IV, as the recognised stock exchange may require.

CHAPTER IV EXIT OPPORTUNITY

9. Applicability of Chapter IV.—The provisions of this Chapter shall apply to any delisting sought to be made under regulation 5 or under clause (b) of regulation 6.

10. Public announcement.—(1) The promoters of the company shall upon receipt of in-principle approval for delisting from the recognised stock exchange, make a public announcement in at least one English National daily with wide circulation, one Hindi National daily with wide circulation and one regional language newspaper of the region where the concerned recognised stock exchange is located.

(2) The public announcement shall contain all material information including the information specified in Schedule I and shall not contain any false or misleading statement.

(3) The public announcement shall also specify a date, being a day not later than thirty working days from

21584075-4

the date of the public announcement, which shall be the 'specified date' for determining the names of shareholders to whom the letter of offer shall be sent.

(4) Before making the public announcement, the promoter shall appoint a merchant banker registered with the Board and such other intermediaries as are considered necessary.

(5) It shall be the responsibility of the promoter and the merchant banker to ensure compliance with the provisions of this Chapter.

(6) No promoter shall appoint any person as a merchant banker under sub-regulation (4) if such a person is an associate of the promoter.

11. Escrow account.—(1) Before making the public announcement under regulation 10, the promoter shall open an escrow account and deposit therein the total estimated amount of consideration calculated on the basis of floor price and number of equity shares outstanding with public shareholders.

(2) On determination of final price and making of public announcement under regulation 18 accepting the final price, the promoter shall forthwith deposit in the escrow account such additional sum as may be sufficient to make up the entire sum due and payable as consideration in respect of equity shares outstanding with public shareholders.

(3) The escrow account shall consist of either cash deposited with a scheduled commercial bank, or a bank guarantee in favour of the merchant banker, or a combination of both.

(4) Where the escrow account consists of deposit with a scheduled commercial bank, the promoter shall, while opening the account, empower the merchant banker to instruct the bank to issue banker's cheques or demand drafts for the amount lying to the credit of the escrow account, for the purposes mentioned in these regulations, and the amount in such deposit, if any, remaining after full payment of consideration for equity shares tendered in the offer and those tendered under sub-regulation (1) of regulation 21 shall be released to the promoter.

(5) Where the escrow account consists of a bank guarantee, such bank guarantee shall be valid till payments are made in respect of all shares tendered under sub-regulation (1) of regulation 21.

12. Letter of offer.—(1) The promoter shall despatch the letter of offer to the public shareholders of equity shares, not later than forty five working days from the date of the public announcement, so as to reach them at least five working days before the opening of the bidding period.

(2) The letter of offer shall be sent to all public shareholders holding equity shares of the class sought to be delisted whose names appear on the register of the company or depository as on the date specified in the public announcement under sub-regulation (3) of

regulation 10.

(3) The letter of offer shall contain all the disclosures made in the public announcement and such other disclosures as may be necessary for the shareholders to take an informed decision.

(4) The letter of offer shall be accompanied with a bidding form for use of public shareholders and a form to be used by them for tendering shares under sub-regulation (1) of regulation 21.

13. Bidding period.—(1) The date of opening of the offer shall not be later than fifty five working days from the date of the public announcement.

(2) The offer shall remain open for a minimum period of three working days and a maximum period of five working days, during which the public shareholders may tender their bids.

14. Right of shareholders to participate in the book building process.—(1) All public shareholders of the equity shares which are sought to be delisted shall be entitled to participate in the book building process in the manner specified in Schedule II.

(2) A promoter or a person acting in concert with any of the promoters shall not make a bid in the offer and the merchant banker shall take necessary steps to ensure compliance with this sub-regulation.

(3) Any holder of depository receipts issued on the basis of underlying shares held by a custodian and any such custodian shall not be entitled to participate in the offer.

(4) Nothing contained in sub-regulation (3) shall affect the right of any holder of depository receipts to participate in the book building process under sub-regulation (1) if the holder of depository receipts exchanges such depository receipts with shares of the class that are proposed to be delisted.

15. Offer price.—(1) The offer price shall be determined through book building in the manner specified in Schedule II, after fixation of floor price under sub-regulation (2) and disclosure of the same in the public announcement and the letter of offer.

(2) The floor price shall not be less than,

(a) where the equity shares are frequently traded in all the recognised stock exchanges where they are listed, the average of the weekly high and low of the closing prices of the equity shares of the company during the twenty six weeks or two weeks preceding the date on which the recognised stock exchanges were notified of the board meeting in which the delisting proposal was considered, whichever is higher, as quoted on the recognised stock exchange where the equity shares of the company are most frequently traded;

- (b) where the equity shares of the company are infrequently traded in all the recognised stock exchanges where they are listed, the floor price determined in accordance with the provisions of sub-regulation (3); or,
- (c) where the equity shares are frequently traded in some recognised stock exchanges and infrequently traded in some other recognised stock exchanges where they are listed, the highest of the prices arrived at in accordance with clauses (a) and (b) above.

Explanation : For the purposes of this sub-regulation, equity shares shall be deemed to be infrequently traded, if on the recognised stock exchange, the annualised trading turnover in such shares during the preceding six calendar months prior to month in which the recognised stock exchanges were notified of the board meeting in which the delisting proposal was considered, is less than five per cent (by number of equity shares) of the total listed equity shares of that class and the term 'frequently traded' shall be construed accordingly.

(3) For the purposes of clause (b) of sub-regulation (2), the floor price shall be determined by the promoter and the merchant banker taking into account the following factors :

- (a) the highest price paid by the promoter for acquisitions, if any, of equity shares of the class sought to be delisted, including by way of allotment in a public or rights issue or preferential allotment, during the twenty six weeks period prior to the date on which the recognised stock exchanges were notified of the board meeting in which the delisting proposal was considered and after that date upto the date of the public announcement; and,
- (b) other parameters including return on net worth, book value of the shares of the company, earning per share, price earning multiple vis-a-vis the industry average.

16. Right of the promoter not to accept the offer price.—(1) The promoter shall not be bound to accept the equity shares at the offer price determined by the book building process.

(2) Where the promoter decides not to accept the offer price so determined :—

- (a) the promoter shall not acquire any equity shares tendered pursuant to the offer and the equity shares deposited or pledged by a shareholder pursuant to paragraphs 7 or 9 of Schedule II shall be returned or released to him within ten working days of closure of the bidding period;
- (b) the company shall not make the final application to the exchange for delisting of the equity shares;

- (c) the promoter may close the escrow account opened under regulation 11; and,
- (d) in a case where the public shareholding at the opening of the bidding period was less than the minimum level of public shareholding required under the listing agreement, the promoter shall ensure that the public shareholding shall be brought up to such minimum level within a period of six months from the date of closure of the bidding through any of the ways mentioned in sub-regulation (3).

(3) For the purposes of clause (d) of sub-regulation (2), the public shareholding may be increased by any of the following ways :

- (a) by issue of new shares by the company in compliance with the provisions of the Companies Act, 1956 and the Guidelines or Regulations of the Board relating to issue of securities and disclosures;
- (b) by the promoter making an offer for sale of his holdings in compliance with the provisions of the Companies Act, 1956 and the Guidelines or Regulations of the Board relating to issue of securities and disclosures; or,
- (c) by the promoter making sale of his holdings through the secondary market in a transparent manner.

17. Minimum number of equity shares to be acquired.—An offer made under Chapter III shall be deemed to be successful if post offer, the shareholding of the promoter (along with the persons acting in concert) taken together with the shares accepted through eligible bids at the final price determined as per Schedule II, reaches the higher of—

- (a) ninety per cent of the total issued shares of that class excluding the shares which are held by a custodian and against which depository receipts have been issued overseas; or
- (b) the aggregate percentage of pre offer promoter shareholding (along with persons acting in concert with him) and fifty per cent of the offer size.

18. Procedure after closure of offer.—Within eight working days of closure of the offer, the promoter and the merchant banker shall make a public announcement in the same newspapers in which the public announcement under sub-regulation (1) of regulation 10 was made regarding :—

- (i) the success of the offer in terms of regulation 17 along with the final price accepted by the acquirer; or
- (ii) the failure of the offer in terms of regulation 19; or
- (iii) rejection under regulation 16 of the final price discovered under Schedule II, by the promoters.

19. Failure of offer.—(1) Where the offer is rejected under regulation 16 or is not successful as per regulation 17, the offer shall be deemed to have failed and no equity shares shall be acquired pursuant to such offer.

(2) Where the offer fails—

- (a) the equity shares deposited or pledged by a shareholder under paragraphs 7 or 9 of Schedule II shall be returned or released to him within ten working days from the end of the bidding period;
- (b) no final application shall be made to the exchange for delisting of the equity shares; and
- (c) the escrow account opened under regulation 11 shall be closed.

20. Payment of consideration and return of equity shares.—(1) The promoter shall immediately on ascertaining success of the offer, open a special account with a banker to an issue registered with the Board and transfer thereto, the entire amount due and payable as consideration in respect of equity shares tendered in the offer, from the escrow account.

(2) All the shareholders whose equity shares are verified to be genuine shall be paid the final price stated in the public announcement within ten working days from the closure of the offer.

(3) The equity shares deposited or pledged by a shareholder pursuant to paragraphs 7 or 9 of Schedule II shall be returned or released to him, within ten working days from the closure of the offer, in cases where the bids pertaining thereto have not been accepted.

21. Right of remaining shareholders to tender equity shares.—(1) Where, pursuant to acceptance of equity shares tendered in terms of these regulations, the equity shares are delisted, any remaining public shareholder holding such equity shares may tender his shares to the promoter upto a period of at least one year from the date of delisting and, in such a case, the promoter shall accept the shares tendered at the same final price at which the earlier acceptance of shares was made.

(2) The payment of consideration for shares accepted under sub-regulation (1) shall be made out of the balance amount lying in the escrow account.

(3) The amount in the escrow account or the bank guarantee shall not be released to the promoter unless all payments are made in respect of shares tendered under sub-regulation (1).

CHAPTER V

COMPULSORY DELISTING

22. Compulsory delisting by a stock exchange.—A recognised stock exchange may, by order, delist any equity shares of a company on any ground prescribed in the rules made under section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956):

Provided that no order shall be made under this sub-regulation unless the company concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) The decision regarding compulsory delisting shall be taken by a panel to be constituted by the recognised stock exchange consisting of—

- (a) two Directors of the recognised stock exchange (one of whom shall be a public representative);
- (b) one representative of the investors;
- (c) one representative of the Ministry of Corporate Affairs or Registrar of Companies; and
- (d) the Executive Director or Secretary of the recognised stock exchange.

(3) Before making an order under sub-regulation (1), the recognised stock exchange shall give a notice in one English national daily with wide circulation and one regional language newspaper of the region where the concerned recognised stock exchange is located, of the proposed delisting, giving a time period of not less than fifteen working days from the notice, within which representations may be made to the recognised stock exchange by any person who may be aggrieved by the proposed delisting and shall also display such notice on its trading systems and website.

(4) The recognised stock exchange shall while passing any order under sub-regulation (1), consider the representations, if any, made by the company as also any representations received in response to the notice given under sub-regulation (3) and shall comply with the criteria specified in Schedule III.

(5) The provisions of Chapter IV shall not be applicable to a compulsory delisting made by a recognised stock exchange under this Chapter.

(6) Where the recognised stock exchange passes an order under sub-regulation (1), it shall,—

- (a) forthwith publish a notice in one English National daily with wide circulation and one regional language newspaper of the region where the concerned recognised stock exchange is located, of the fact of such delisting, disclosing therein the name and address of the company, the fair value of the delisted equity shares determined under sub-regulation (1) of regulation 23 and the names and addresses of the promoters of the company who would be liable under sub-regulation (3) of regulation 23; and
- (b) inform all other stock exchanges where the equity shares of the company are listed, about such delisting and the surrounding circumstances.

23. Rights of public shareholders in case of a compulsory delisting.—(1) Where equity shares of a company are delisted by a recognised stock exchange under this Chapter, the recognised stock exchange shall appoint an independent valuer or valuers who shall determine the fair value of the delisted equity shares.

(2) The recognised stock exchange shall form a panel of expert valuers from whom the valuer or valuers shall be appointed for purposes of sub-regulation (1).

(3) The promoter of the company shall acquire delisted equity shares from the public shareholders by paying them the value determined by the valuer, subject to their option of retaining their shares.

Explanation : For the purposes of sub-regulation (1),—

- (a) 'valuer' means a chartered accountant within the meaning of clause (b) of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), who has undergone peer review as specified by the Institute of Chartered Accountants of India constituted under that Act, or a merchant banker appointed to determine the value of the delisted equity shares;
- (b) value of the delisted equity shares shall be determined by the valuer having regard to the factors mentioned in regulation 15.

24. Consequences of compulsory delisting.—Where a company has been compulsorily delisted under this Chapter, the company, its whole time directors, its promoters and the companies which are promoted by any of them shall not directly or indirectly access the securities market or seek listing for any equity shares for a period of ten years from the date of such delisting.

CHAPTER VI

POWERS OF THE BOARD

25. Power of the Board to issue clarifications.—In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications and guidelines in the form of circulars.

26. Directions by the Board.—Without prejudice to provisions of the Act and those of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board may in case of any violation of these regulations and in the interests of the investors and the securities market give such directions as it deems fit:

Provided that the Board shall, either before or after passing such orders, give an opportunity of hearing to the concerned person.

CHAPTER VII

SPECIAL PROVISIONS FOR SMALL COMPANIES AND DELISTING BY OPERATION OF LAW

27. Special provisions in case of small companies.—

(1) Where a company has paid-up capital upto one crore rupees and its equity shares were not traded in any recognised stock exchange in the one year immediately preceding the date of decision, such equity shares may be delisted from all the recognised stock exchanges where they are listed, without following the procedure in Chapter IV.

(2) Where a company has three hundred or fewer public shareholders and where the paid-up value of the shares held by such public shareholders in such company is not more than one crore rupees, its equity shares may be delisted from all the recognised stock exchanges where they are listed, without following the procedure in Chapter IV.

(3) A delisting of equity shares may be made under sub-regulation (1) or sub-regulation (2) only if, in addition to fulfilment of the requirements of regulation 8, the following conditions are fulfilled:

- (a) the promoter appoints a merchant banker and decides an exit price in consultation with him;
- (b) the exit price offered to the public shareholders shall not be less than the price arrived at in consultation with the merchant banker;
- (c) the promoter writes individually to all public shareholders in the company informing them of his intention to get the equity shares delisted, indicating the exit price together with the justification therefore and seeking their consent for the proposal for delisting;
- (d) at least ninety per cent of such public shareholders give their positive consent in writing to the proposal for delisting, and have consented either to sell their equity shares at the price offered by the promoter or to remain holders of the equity shares even if they are delisted;
- (e) the promoter completes the process of inviting the positive consent and finalisation of the proposal for delisting of equity shares within seventy five working days of the first communication made under clause (c);
- (f) the promoter makes payment of consideration in cash within fifteen working days from the date of expiry of seventy five working days stipulated in clause (e).

(4) The communication made to the public shareholders under clause (c) of sub-regulation (3) shall contain justification for the offer price with particular reference to the applicable parameters mentioned in regulation 15 and specifically mention that consent for the proposal would include consent for dispensing with the exit price discovery through book building method.

(5) The concerned recognised stock exchange may delist such equity shares upon satisfying itself of compliance with this regulation.

28. Delisting in case of winding up, derecognition, etc.—(1) In case of winding up proceedings of a company whose equity shares are listed on a recognised stock exchange, the rights, if any, of the shareholders of such company shall be in accordance with the laws applicable to those proceedings.

(2) Where the Board withdraws recognition granted to a stock exchange or refuses renewal of recognition to it, the Board may, in the interest of investors pass appropriate order in respect of the status of equity shares of the companies listed on that exchange.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

29. Recognised stock exchanges to monitor compliance.—The respective recognised stock exchanges shall comply with and monitor compliance with the provisions of these regulations and shall report to the Board any instance of non-compliance which comes to their notice.

30. Listing of delisted equity shares.—No application for listing shall be made in respect of any equity shares,

- (a) which have been delisted under Chapter III or under Chapter VII (except regulation 27), for a period of five years from the delisting;
- (b) which have been delisted under Chapter V, for a period of ten years from the delisting.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), an application for listing of delisted equity shares may be made where a recommendation in this regard has been made by the Board for Industrial and Financial Reconstruction under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.

(3) While considering an application for listing of any equity shares which had been delisted the recognised stock exchange shall have due regard to facts and circumstances under which delisting was made.

(4) An application for listing made in respect of delisted equity shares shall be deemed to be an application for fresh listing of such equity shares and shall be subject to provisions of law relating to listing of equity shares of unlisted companies.

31. Transitional provisions.—(1) Anything done or omitted to be done or any right, privilege, obligation or liability acquired or accrued or incurred under Securities and Exchange Board of India (Delisting of Securities) Guidelines, 2003 prior to the commencement of these regulations shall be governed by said guidelines.

(2) Any application for delisting made by any company or any promoter or acquirer who wanted to delist securities of the company, prior to commencement of these regulations and pending with any recognised stock exchange as on the date of such commencement shall be proceeded with under the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Securities) Guidelines, 2003.

(3) The remaining procedures in respect of an exit opportunity already completed or an exit opportunity initiated but not completed under the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Securities) Guidelines,

2003 prior to commencement of these regulations, shall be completed and the application for delisting made pursuant thereto shall be dealt under the said guidelines.

SCHEDULE I

[See Regulation 10(2)]

CONTENTS OF THE PUBLIC ANNOUNCEMENT

1. The floor price and the offer price and how they were arrived at.
2. The dates of opening and closing of the offer.
3. The name of the exchange from which the equity shares are sought to be delisted.
4. The manner in which the offer can be accepted by the shareholders.
5. Disclosure regarding the minimum acceptance condition for success of the offer.
6. The names of the merchant banker and other intermediaries together with the help line number for the shareholders.
7. The specified date fixed as per sub-regulation (3) of regulation 10.
8. The object of the proposed delisting.
9. The proposed time table from opening of the offer till the payment of consideration or return of equity shares.
10. Details of the escrow account and the amount deposited therein.
11. Listing details and stock market data:
 - (a) high, low and average market prices of the equity shares of the company during the preceding three years;
 - (b) monthly high and low prices for the six months preceding the date of the public announcement; and,
 - (c) the volume of equity shares traded in each month during the six months preceding the date of public announcement.
12. Present capital structure and shareholding pattern.
13. The likely post-delisting shareholding pattern.
14. The aggregate shareholding of the promoter together with persons acting in concert and of the directors of the promoter where the promoter is a company and of persons who are in control of the company.
15. A statement, certified to be true by the board of directors of the company, disclosing material deviation, if any, in utilisation of proceeds of issues of securities made during the five years immediately preceding the date of public announcement, from the stated object of the issue.
16. A statement by the board of directors of the company confirming that all material information which is required to be disclosed under the provisions of continuous listing requirement have been disclosed to the stock exchanges.
17. Name of compliance officer of the company.

18. It should be signed and dated by the promoter. Where the promoter is a company, the public announcement shall be dated and signed on behalf of the board of directors of the company by its manager or secretary, if any, and by not less than two directors of the company, one of whom shall be a managing director where there is one.

SCHEDULE II

[SEE REGULATION 15(1)]

THE BOOK BUILDING PROCESS

1. The book building process shall be made through an electronically linked transparent facility and the promoter shall enter into an agreement with a stock exchange for the purpose.

2. The public announcement and letter of offer shall be filed without delay with the stock exchange mentioned in paragraph 1 and such stock exchange shall forthwith post the same in its website.

3. The minimum number of bidding centres shall be :

- (a) the four metropolitan centres situated at Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai;
- (b) such cities in the region in which the registered office of the company is situated, as are specified by the stock exchange mentioned in paragraph 1.

4. There shall be at least one electronically linked computer terminal at all bidding centres.

5. The shareholders may withdraw or revise their bids upwards not later than one day before the closure of the bidding period. Downward revision of bids shall not be permitted.

6. The promoter shall appoint 'trading members' at the bidding centres, whom the public shareholders may approach for placing bids on the on-line electronic system.

7. The shareholders holding dematerialised shares desirous of availing the exit opportunity may deposit the equity shares in respect of which bids are made, with the special depositories account opened by the merchant banker for the purpose prior to placement of orders or, alternately, may mark a pledge for the same to the merchant banker in favour of the said account.

8. The merchant banker shall ensure that the equity shares in the said special depositories account are not transferred to the account of the promoter unless the bids in respect thereof are accepted and payments made.

9. The holders of physical equity shares may send their bidding form together with the share certificate and transfer deed to the trading member appointed for the purpose, who shall immediately after entering their bids on the system send them to the company or the share transfer agent for confirming their genuineness. The company or the share transfer agent shall deliver the certificates which are found to be genuine to the merchant banker, who shall not make it over to promoter unless the bids in respect

thereof are accepted and payment made. The bids in respect of the certificates which are found to be not genuine shall be deleted from the system.

10. The verification of physical certificates shall be completed in time for making the public announcement under regulation 18.

11. The bids placed in the system shall have an audit trail which includes stock broker identification details, time stamp and unique order number.

12. The final offer price shall be determined as the price at which the maximum number of equity shares is tendered by the public shareholders. If the final price is accepted, then, the promoter shall accept all shares tendered where the corresponding bids placed are at the final price or at a price which is lesser than the final price. The promoter may, if he deems fit, fix a higher final price.

SCHEDULE III

[See Regulation 22(4)]

CRITERIA FOR COMPULSORY DELISTING

1. The recognised stock exchange shall take all reasonable steps to trace the promoters of a company whose equity shares are proposed to be delisted, with a view to ensuring compliance with sub-regulation (3) of regulation 23.

2. The recognised stock exchange shall consider the nature and extent of the alleged non-compliance of the company and the number and percentage of shareholders who may be affected by such non-compliance.

3. The recognised stock exchange shall take reasonable efforts to verify the status of compliance of the company with the office of the concerned Registrar of Companies.

4. The names of the companies whose equity shares are proposed to be delisted and their promoters shall be displayed in a separate section on the website of the recognised stock exchange for a brief period of time. If delisted the names shall be shifted to another separate section on the website.

5. The recognised stock exchange shall in appropriate cases file prosecutions under relevant provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or any other law for the time being in force against identifiable promoters and directors of the company for the alleged non-compliances.

6. The recognised stock exchange shall in appropriate cases file a petition for winding up the company under section 433 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or make a request to the Registrar of Companies to strike off the name of the company from the register under section 560 of the said Act.

K. M. ABRAHAM, Whole Time Member

[ADVT III/4/Exty./692B/09]